have been taken over by M.C.D. in anticipation of payment of deficiency charges by D.D.A. These are being worked out by MCD on the basis of information furnished by D.D.A.

Area under irrigation

2003. SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ :
DR. H.P. SHARMA :
SHRIMATI MAIMOONA SULTAN :

will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) what is the present area under irrigation and what percentage of the total area under cultivation does it constitute ;

(b) what is the additional area to be brought under irrigation during the Seventh five Year Plan ; and

(c) the extent of the total irrigation potential which is at present utilised and the percentage of it that will be utilised by the end of the seventh Five Year Plan ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) As per Land Use statistics for 1981-82 (Provisional), the gross irrigated area in the country is 51-61 M. Ha. constituting about 29.15 percent of the total cropped area in the country.

(b) The additional irrigation potential proposed to be created during the Seventh Plan is about 12.9 M.Ha.

(c) About 89% of the potential is utilised at present and this is expected to increase to 94.5% by the end of the Seventh Plan period.

Post-tax return on capital employed in fer... stry

2004. SHRI ...UMAR BIRLA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what is the post-tax return on capital employed permitted to fertiliser industry ; and

(b) whether Government propose increasing of such return so as to improve its working and boost the expansion of fertilizer industry for meeting the shortage of fertilizers in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS (SHRI K. NATWAR SINGH) : (a) Under the present retention price scheme, the fertilizer industry is allowed a post-tax return of 12% on 'net-worth' (not on 'capital employed').

(b) No, Sir.

मध्य प्रदेश को तिलहनों की सप्लाई में कमी

2005. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मध्य प्रदेश को मूंगफली, राई, सरसों और तोरया के तिलहनों की मिनिकिटों की सप्लाई में कमी किए जाने के क्या कारण हैं, जबकि ये मिनिकिटें अपनी उपयोगिता के कारण किसानों में लोकप्रिय हैं ;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को 1985-86 के दौरान तिलहन फसलों के 1,69,300 बीज के मिनिकिट आवंटित किए हैं । यदि वे चाहें तो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उसे वित्तीय नियतन में से किसी विशेष तिलहन के और मिनिकिट प्राप्त करने का राज्य सरकार को अधिकार है ।

मध्य प्रदेश ... धान के उन्नत बीजों का ...

2... **प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या कृ... ह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कृषकों में गेहूं व धान की उन्नत किस्म के बीजों के इस्तेमाल को

लोकप्रिय बनाने के लिए अनुदान की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

कृषि [illegible]
मंत्री (योगेन्द्र [illegible]) : (क) मध्य प्रदेश में 150 रु० प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा पर गेहूं के बीजों के वितरण पर [illegible] देने हेतु कृषि लागत और [illegible] की सिफारिश के अनुपालन में राज्य सरकार ने कृषि और सहकारि[illegible] सुझाव किया था कि [illegible] सिफारिश की गई राज [illegible] को केन्द्रीय सरकार द्वारा [illegible] चाहिए । राज्य सरकार [illegible] बीजों के मिनिकिटों का वितरण करने के लिए और धान के बीजों को रियायती दरों पर किसानों को मुहैया करने के लिए भी अनुदान सहायता मांगी थी।

[illegible]य प्रदेश में गेहूं के बीजों के [illegible] पर राज सहायता हेतु सिफारिश के संबंध में कृषि लागत और मूल्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि [illegible] खेती की कुल लागत में बीज [illegible] प्रतिशत पंजाब और हरियाणा राज्यों में खेती की कुल लागत में बीज की लागत के प्रतिशत मुकाबले अधिक थी ।

[illegible]श और अन्य राज्यों में खेती [illegible] आयोग से प्राप्त किया [illegible] वर्ष 1981–82 और 1982–83 के [illegible] और हरियाणा में खेती की [illegible] विश्लेषण किया गया था । विश्ले[illegible] पता चलता है कि मध्य प्रदेश में गे[illegible] की लागत में बीजों की लागत उतनी ही थी जितनी कि हरियाणा और पंजाब के मामले में यह सीमांततः कम थी परन्तु यह अन्तर कोई विशेष नहीं था । दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मामले में उर्वरक का उपयोग काफी कम पाया गया और इस कारण से मुख्यतः मध्य प्रदेश में खेती की कुल लागत की प्रतिशतता में प्रति हैक्टायर बीजों के उपयोग पर व्यय अधिक बैठता है । तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि कृषि आदानों के वैज्ञानिक प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि करके मध्य प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है । चूंकि बीजों की लागत पर राज्य सहायता उपलब्ध करा कर इस प्रयोजन को प्राप्त नहीं किया जा सका, अतः यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में गेहूं के बीजों पर राज सहायता उपलब्ध न कराई जाए ।

तथापि राज्य सरकार [illegible] की कि राज्य में गेहूं [illegible] करने के लिए एक [illegible] गेहूं विकास कार्यक्रम बनाया जाए ।

[illegible]हां तक धान [illegible] है । पूर्वी मध्य [illegible] 40 चुने हुए ब्लाकों में धान के बीजों के मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण करने तथा धान के बीजों के वितरण पर राज सहायता देने हेतु 126 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है । इसे केन्द्र और राज्य के [illegible] 50 : 50 के अनुपात में वहन किया [illegible] यह चावल मिनिकिट एवं सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के चावल के मिनिकिट के निःशुल्क वितरण हेतु मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराई जा रही 100 प्रतिशत सहायता के अतिरिक्त है । इस योजना के तहत वर्ष 1985–86 के लिए मध्य प्रदेश हेतु 39.90 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है ।

Re[illegible]
V[illegible]

2007. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of INFORMATION [illegible]CASTING be pleased

(a) whether the Ind[illegible] Eastern Newspapers Society made any representation for reconsideration of the Directorate of Audio Visual Publicity rates ;

(b) if so, what action Government have taken in this matter ; and